"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगदी भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2003—भाद्र 28, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. (1973), के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर उन्हें, आगामी आदेश पर्यन्त, अस्थायी रूप से, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री पंकज द्विवेदी, भा. प्र. से. (ए. पी. 1975), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य से मुक्त किया जाता है.

3. श्री टी. एस. छतवाल, भा. प्र. से. (1984), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को, आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थ करने के लिये इनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी जाती है. श्री छतवाल को आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

4. श्री मंशाराम ठाकुर, भा. प्र. से. (1991) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए, उन्हें आगामी आदेश पर्यन्त, अस्थायी रूप से, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर दिनांक 6 सितम्बर 2003

क्रमांक 1923/1592/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री एस. के. तिवारी, सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग रायपुर को दिनांक 2-8-2003 से 7-8-2003 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री तिवारी को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. श्री तिवारी अवकाश से लौटने पर पुन: सचिव, छ. ग. लोक आयोग में पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री तिवारी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2003

क्रमांक 1932/1672/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—डॉ. बी. एस. अनंत, कलेक्टर, जशपुर को दिनांक 8-9-2003 से 12-9-2003 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14-9-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी तरह देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनंत यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, कलेक्टर, जशपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

5. डॉ. अनंत के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री नीलम नामदेव एक्का, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक 1706/28/2003.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, राज्य शासन, एतद्द्वारा तत्कालीन रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर चिरहूलडीह आवासीय योजना क्रमांक 9, जिसका अभिन्यास तत्कालीन नगर सुधार न्यास, रायपुर द्वारा अनुमोदित कराया गया था, के खसरा नंबर 115, 78, 103, 89/11, 89/1, 77, 120, 75/3, 89/3, 126/3, 126/5, 89/7, 76, 111, 110, 75/4, 102, 67, 126/1, 98/5, 74, 89/5, 107, 116, 82, 109, 75/2, 89/4, 89/13, 117/2, 112, 118, 113, 98/5, 89/12 तथा समता कालोनी के भूखंड क्रमांक ई-160 में निहित कुल रकबा 1.68 एकड़ में पूर्व निर्धारित अभिन्यास से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-7-8/2002/ (छै:)/11.—राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-16/3/92 ग्यारह-ब दिनांक 27-6-1992 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में कण्डिका 3 (ख) में शब्दावली "प्रभावी दिनांक के 8 वर्ष अथवा शून्य दिनांक 11 वर्ष" के स्थान पर "प्रभावी दिनांक के 13 वर्ष अथवा शून्य दिनांक के 16 वर्ष"

प्रतिस्थापित किया जाता है.

उक्त संशोधन 27 जून 1992 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 3-88/दो/गृह/2003.—राज्य शासन एतद्‌द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं.-2) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्र को प्रस्तावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करता है.

1. नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (2) में वांछित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कालम नं. (4) की तत्संबंध प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है.

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कालम नं. (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कालम नं. (3) तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जावे.

सारणी

क्रमांक	पुलिस थाने का नाम जहां से अपवर्जित किया जाना है	उस पुलिस थाने का नाम जिसमें शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना मालखरौदा	पुलिस चौकी हसौद.	मिरौनी	15
2.	—''—	—''—	मुडपार	15
3.	—''—	—''—	नरियर	15
4.	—''—	—''—	धमनी	15
5.	थाना मालखरौदा	पुलिस चौकी हसौद.	आमोदा	36
6.	—''—	—''—	परसदा	37
7.	—''—	—''—	धमनी	37
8.	थाना डभरा	—''—	मरघटी	16

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2003

क्रमांक 5448/4027/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री के. पी. पाठक, संयुक्त कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को रायगढ़ जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नियुक्त करता है तथा यह निर्देश देता है कि वे उक्त संहिता के अधीन तथा तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला-मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2003

क्रमांक 5571/डी-4122/21-ब/छग/03.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा मो. जाहिद खान, अधिवक्ता अंबिकापुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट अंबिकापुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 29-2-2004 तक के लिये अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट की समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

Raipur, the 9th September 2003

No. 5583/4168/XXI-B/Ch./03.—In supersession of all previous notifications issued on the subject by any authority prior to the 1st November, 2000, the Governor of Chhattisgarh is pleased to make the following rules in regard to the publication of the Indian Law Reports, Chhattisgarh Series, namely :—

1. These rules shall be called Indian Law Reports, Chhattisgarh Series Rules, 2003.

2. These rules shall come in force on the date of their publication in Chhattisgarh Gazette.

3. The staff for editing the Indian Law Reports, Chhattisgarh Series shall consist of an Editor and an Assistant Editor.

4. (a) The Editor shall be appointed by the Governor on the recommendation of the Chief Justice.

(b) For being appointed the Editor of I.L.R. one must be a practicing Advocate of merit. The Editor shall be appointed for five years, but he may be re-appointed for another term of five years. Ordinarily no person shall be appointed as an Editor after the age of sixty years.

(c) The Editor shall be appointed on part-time basis and he shall be paid such honorarium as may be fixed by the Governor from time to time.

(d) The Governor may, at any time, on the recommendation of the Chief Justice, dispense with the services of the Editor after giving him one month's notice.

5. (a) The Assistant Editor shall be a regular employee on the Establishment of the High Court and shall be appointed by the Chief Justice in the pay scale of Rs. 6500-200-10500.

(b) The conditions of service of the Assistant Editor shall be the same as that of other officers of the High Court Establishment of the same pay scale.

6. There shall be a Committee to guide and supervise the editorial work of the Indian Law Reports, Chhattisgarh Series.

7. The Committee shall be constituted as follows :—

(a) One Honourable Judge of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur to be nominated by the Chief Justice.

(b) Three Advocates practicing in the High Court to be nominated by the Chief Justice.

(c) The Advocate General.

(d) The Editor shall be Secretary of the Committee.

8. The Assistant Editor shall select.—

(i) all cases marked 'R' by the presiding Judge or Judges.

(ii) cases considered by him as suitable for reporting and bringing them to the notice of the Editor who will select cases out of them for reporting.

(iii) cases in clause (1) shall be circulated amongst the members of the Committee. If the majority of the members approve the reporting of the case, they shall be reported; but if they do not approve, the cases shall be submitted to the Judge or Judges concerned with their opinion and the opinion of the Judge or Judges concerned shall be final.

(iv) cases in clause (ii) shall be circulated amongst the members of the Committee and only such cases as are recommended by majority of them and approved by the Judge or Judges concerned

shall be reported.

9. The Committee with the previous approval of the Chief Justice may make rules for the conduct of business of the Committee.

10. The Report of cases shall be published under the authority of the STATE GOVERNMENT and the Committee is empowered to publish them under such authority.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2003

क्रमांक/एफ-73-57/03/उ. शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत विश्वभारती विश्वविद्यालय रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उपनियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है, तथा उपनियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 22 प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

VISWA BHARATHI UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (Chhattisgarh Adhiniyam No.2 of 2002), vide Notification of the Government of chhattisgarh No. F73-57/2003/HE/38 Dated 26th May 2003 and notified vide Gazette publication dated 6th June 2003

FIRST STATUTES

Made in accordance with the provisions under section 25 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (Chhattisgarh Adhiniyam No. 2 of 2002)

1. Short Title, Extent and Commencement

1. These Statutes shall, here-in after be called, "The FIRST STATUTES of Viswa Bharathi University, Raipur, 2003 ".

2. The First Statutes are applicable to 'Viswa Bharathi University', Raipur and any matter relating and/or incidental thereto.

3. The First Statutes shall come into force on the date of publication of the First Statutes by the Government of Chhattisgarh in the Official Gazette.

4. The Registered office of the Viswa Bharathi University, Raipur shall be situated at, Raipur, Dist. Raipur, Chhattisgarh.

2. Definitions

In these First Statutes, unless the context demands otherwise:

1. Act means, the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (Chhattisgarh Adhiniyam No. 2 of 2002).

2. Academic Year means the period from July 1 of any year to June 30 of the following year or the date specified by the Academic council for a particular academic session.

3. Academic centres mean Distance Education centres approved by the University for imparting education in formal mode in respect of any or all courses offered by the University and even in courses not offered by the university but approved by the University and located within or outside the state of chhattisgarh in India and abroad .Such centers shall be designated as Academic centers and shall function independently within the framework of the University rules and regulations.

4. Ad-hoc committee means a committee constituted under Section 14.0 of these First Statutes.

5. Affiliation means and includes recognition of institutions, colleges and schools, association of Institutions, Colleges and schools located in or outside the state of Chhattisgarh including overseas, and admission of such institutions, colleges and schools under the University for the purpose of conducting the formal and informal educational, professional and vocational programs of the University.

6. Authorities mean authorities mentioned under Section 19 of the Act and under Sections 8; 9, 10 of these First Statutes.

7. Academic Council means the Academic Council constituted under Section 22 of the Act and under Section 10.0 of these First Statutes.

8. Board means the Board of Management of the University constituted under Section 21 of the Act and Section 9.0 of these First Statutes.

9. Board of studies means the Board of studies of the University for each subject or group of subjects constituted by the Academic Council.

10. Chancellor means the Chancellor of the University as mentioned in Section 14 of the Act and Section 4.0 of these First Statutes.

11. Committee means any committee constituted under Sections 9.(4)(vi),11,12,13 and 14 of these First statutes.

12. Common Seal means the authoritative seal of the University established under Section 6 of the Act.

13. Course includes programs and courses of studies imparted in the formal mode and / or in the informal (non-formal) / distance education mode and /or in the virtual campus in the institution, college, school and/ or Study Centre of the University.

14. Dean (Expansion and Development) means the person responsible for the upkeep, development and proper utilization of infrastructure of the respective school/college and fulfills the academic requirements of the systems.

15. Dean (Planning Implementation and monitoring) means the person responsible for the preparation, implementation and monitoring of plans of the university.

16. Dean (Research) means the person responsible for the execution and monitoring of the research schemes.

17. Dean (Students Welfare) means person responsible for looking after the campus amenities and general welfare of the students of the schools, institutions and colleges of the university.

18. Dean (Discipline) means the person responsible for maintaining the discipline amongst the students of schools, college of the university.

19. Dean (Faculty) means persons responsible for monitoring the academic activities of the faculty concerned.

20. Dean (Informal Education) means person responsible for planning, implementation and monitoring of Informal Education plans of the University.

21. Director means officer appointed by the Board of Management for coordinating the functions and activities of the schools, colleges, Study Centres in respect of which he is appointed.

22. Distance education means the education / courses programs offered to the student at different places in India and abroad through correspondence/study material and contact-classes. It includes system of imparting education through any means of Communications such as broadcasting, contact programs, internet, e-learning or the combination of any two or more of such means.

23. Fund means the fund established under Section 7 of the Act.

24. Financial Year means the period commencing on the 1st April of any year and ending with 31st March of the following year.

25. Finance Committee means the Finance Committee constituted under Section 23 of the Act and Section 13.0 of these First Statutes.

26. Government means the Government of the State of Chhattisgarh.

27. He includes She and His includes Her;

28. Institute means and includes institute, institution, school and college constituted as part of the University to impart education in the specified disciplines, located within or outside the state of Chhattisgarh in India and/ or abroad.

29. Manual of Instructions means and includes all rules, procedures, instructions and systems laid down by various committees, Boards, authorities, Officers of the University for the purpose of smoothly conducting the business of the University.

30. OFF-Campus programme center means and includes an institution, college, school in or out side State of Chhattisgarh or in any part of India or abroad authorised by the University in writing to conduct all or any number of program/courses offered by the University according to the rules and regulations as prescribed by the University and/or terms and conditions as may be specified by the University and agreed upon by the Institution, College or School.

31. Ordinance means ordinance issued by the University as prescribed by Section 27 of the Act.

32. Rules mean the Rules made under Section 36 of the Act.

33. Regulations mean Regulations made under Section 37 of the Act.

34. Regional Campus means the campus of the University Colleges, Institutions and Schools located in and outside Raipur, in side the state of Chhattisgarh or in any part of India and/or abroad . Such regional Campuses for convenience may be designated as Bhilai Campus, Bhilaspur Campus, Banglore Campus, Delhi Campus, London Campus, Washington Campus etc.

35. State means any State of India established under the relevant legislation of the Parliament.

36. Statutes mean the Statutes made under Section 25 and 26 of the Act and include the amendments, alternations and modifications made there to.

37. Sponsor means the Viswa Bharathi Educational Development of Society registered at Raipur under the provisions of Chhattisgarh Panjikaran Adhiniyam , 1973 vide Society Registration No. 510 Chhattisgarh State, Dated 21-05-2003.

38. Student means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any course of study at the University at main campus and Regional Campuses, any institute of the University, Study Centres, Academic centers off-campus programme center and colleges affiliated to the University.

39. Staff mean the teaching and non-teaching employees of the university who are on direct permanent payroll of the University and do not include any casual, temporary, contractual, ad-hoc employees or visiting persons who may be engaged for a specific assignment or task.

40. Study Centres means Distance Education Centres approved by the University for imparting education in the formal, informal (non-formal) and distance mode in respect of any or all courses offered by the university and located within or outside the state of chhattisgarh or in India or abroad.

41. Standing committee means a committee constituted under Section 14.0 of these First Statutes.

42. University means the Viswa Bharathi University, Raipur established under Section 5 of the Act and will have the same meaning as stated in section 2(f) of the University Grants Commission Act, 1956 as amended from time to time.

43. Vice-chancellor means the Vice-chancellor of the University appointed within the meaning of Section 15 of the Act and Section 5.0 of these First Statutes.

44. Virtual Campus includes the education / courses / programs provided to students through E-learning / website / CD-ROM etc.

45. Visitor means the Visitor as defined under Section 13 of the Act.

3. Objects of the University

The main objectives of the University are as follows:

1. To provide instruction, teaching and training in the field of higher education; and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge.

2. To establish a campus at Raipur in the State of Chhattisgarh and to have affiliated institutions, colleges, schools, and approved study centers Academic Centres, Off Campus programme Centres /Institutions and to establish Regional Campus(es) at different places in India and other countries.

3. To create higher levels of intellectual abilities.

4. To establish state of the art facilities for education, training and research.

5. To offer programs through multi modal form of education.

6. To institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination, or any other mode of evaluation and assessment as laid down by the academic council.

7. To ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions of high standard.

8. To offer continuing distance education both formal and/or informal.

9. To affiliate, recognize or collaborate with any other college, University, Research institution, industry association , professional association, or to develop and run specific educational research programs, training programs, exchange programs and any such programs which the university may consider appropriate for students, faculty members and others.

10. To confer honorary degrees and other academic distinctions in the manner laid down in the Statutes.

11. To encourage and promote research activities and set up independent research institutions for pure and applied research, and institute awards and fellowships at institutions other than the University for undertaking research.

12. To affiliate or collaborate with any other college or university, research institution, industry association, professional association or any other organization, in India or overseas, to conceptualize, design and develop specific educational and research programs, training programs and exchange programs for students, faculty members and others.

13. To recognize the various courses and programs offered by the individuals, institutions, and organizations in various streams of education offered in the multimode methodology of teaching.

14. To undertake surveys, studies and consultancy for any organization in India or overseas.

15. To undertake programs of the training and development of faculty members of the University and other institutions in India or overseas.

16. To undertake collaborative research with any organization in India or overseas, and undertake commercialization of technologies.

17. To develop, register and license all forms of intellectual property rights, including, interalia, trademarks, copyrights, know-how and patents etc.

18. To conceptualize, design, develop and commercialize various products, equipment and machinery as part of the research and development activity.

19. To provide " Education For All" which includes Formal and Informal modes of instruction keeping in view the literacy and the educational needs of deprived sections of the society by establishing informal educational centers in and out side the state of Chhattisgarh, to achieve cent percent literacy and education at least up to the level of Matriculation.

20. To bring higher education with in the reach of Majority of the youth aspiring higher qualification and / or research by a network of formal institutions such as regional campuses, off-campus programme centres and academic centres through out the country in accomplishment of the prime objective "Desired Education For All" .

21. To encourage sports, cultural, extra curricular and co-curricular activities for students and staff.

22. To do all things necessary or expedient to promote the above objectives.

23. To pursue any other objective as may be approved by the Board.

4.0 Appointment and powers of the Chancellor

1. Appointment :

   i. The Chancellor shall be appointed by the Sponsor with the prior approval of the Visitor.

   ii. The term of office of the Chancellor shall be three years, and he may be re-appointed for successive terms, at the pleasure of the Sponsor.

   iii. The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and Head of the University.

   iv. The Chancellor shall preside over the Convocation of the University, when the visitor is not present.

2. Powers :

   The Chancellor shall have the following powers:

   i. To call for any information on record.

   ii. To appoint the Vice-Chancellor.

   iii. To remove the Vice-Chancellor.

   iv. Such other powers as may be delegated to him by the Governing Body.

   v. In absence of the Vice-Chancellor due to any reason, the Chancellor can appoint any suitable person to perform all the functions of the Vice-Chancellor.

   vi. If in the opinion of the Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report with in seven days, his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter.

   vii. The office of the Chancellor may be located anywhere in India or overseas.

Explanation :

i. Provided that if in the opinion of the authority concerned such action should not have been taken by the Chancellor then such case shall be referred to the Governing Body whose decision thereon shall be final.

ii. Provided further that where any such action taken by the Chancellor affects any person in the service of the University such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Body and the Governing Body may confirm or modify or reverse the action taken by the Chancellor.

3. Removal of the Chancellor :

   i. If in the opinion of the Sponsor, the actions of the Chancellor are found to be in any way detrimental to the interests of the University, the Sponsor shall appoint such other person as may be found appropriate in the position of Chancellor to succeed the person so acting.

   ii. Provided that, the Sponsor shall seek the approval of the Visitor before appointing such other person as the Chancellor. The Sponsor may stipulate the date from which such other person shall assume the office of the Chancellor.

4. Remuneration of the Chancellor
   The Sponsor from time to time decides on the Honorarium and / or the pay and / or allowances to be paid to the Chancellor and / or prerequisites to be provided to the Chancellor.

5.0 Appointment, Powers and responsibilities of the Vice-Chancellor

1. Appointment :

   i. The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body. The recommendation of the name(s) for the post Vice-Chancellor will be done after the due approval of the Sponsor.
   ii. The term of office of the Vice-Chancellor shall initially be Four years, and he may be re-appointed for successive term(s) by the Chancellor after due approval of the Sponsor.

2. Powers :

   i. The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and also the ex-officio member of the Governing Body, Board of Management, Academic Council, and such other Committees that may be set up by the Governing Body or by the Board from time to time.

   ii. In absence of the Visitor and Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the Convocation.

   iii. If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter within seven days.

   iv. If in the opinion of the Vice-Chancellor any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by the Act, Statutes or Ordinances or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the authority concerned to revise its decision within seven days from the date of his decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within seven days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

Explanation :

i. Provided that if in the opinion of the authority concerned such action should not have been taken by the Vice-Chancellor then such case shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

ii. Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

3. Responsibilities :

The Vice Chancellor shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the various authorities of the University, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Act and the Statutes.

4. Removal :

i. If at any time upon representation being made or otherwise, and after making such enquiries as may be deemed necessary, the Chancellor with approval / recommendation of Sponsor by an order in writing stating the reasons therein, may ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

ii. If in the opinion of the Sponsor, the actions of the Vice-Chancellor are found to be in any way detrimental to the interests of the University, the Sponsor can recommend the Chancellor to appoint such other person as may be found appropriate in the position of Vice-Chancellor to succeed the person so acting. The Sponsor may stipulate the date from which such other person shall assume the office of the Vice-Chancellor.

6.0 Appointment, Term , powers, Responsibilities and Removal of the Registrar

1. Appointment

i. The Registrar shall be appointed by the Vice-Chancellor, based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose, with the approval of the Chancellor.

The Registrar shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

ii. The selection committee shall consist of the following members:

a. The Vice-Chancellor - Chairman

b. One representative of the Chancellor.

c. One representative of the Sponsor who is also a member of the Governing Body.

d. One expert nominated by the Board of Management, who is not in any way connected with the University.

iii. Appointment by Deputation

In case the formation of search committee and/or appointment of Registrar indefinitely postponed or delayed due to extraordinary reasons, the sponsor may depute the Registrar for such term as it deems appropriate.

2. Term :

The term of office of the Registrar shall be as mentioned in the order of his appointment by the Vice-Chancellor.

3. Powers :

i. The Registrar shall be the ex-officio secretary of the Governing Body, Board of Management, the Academic Council and such other authorities and bodies as may be constituted by or under the Act or the Statutes or the Ordinances.

ii. To collect all income and disburse the same for the purpose of the University as sanctioned by the Vice-Chancellor or Board of Management

iii. To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and perform pleadings or depute his representatives for this purpose.

iv. To enter into agreements, contracts on behalf of the University and make amendments and alterations in terms of such agreements or contracts as may be directed by the Board.

v. To sign documents and authenticate records on behalf of the University.

4. Duties and Responsibilities

The following shall be the duties of the Registrar:

i. The Registrar shall undertake such functions as may be specified by the Governing Body or the Board of Management or the Vice-Chancellor.

ii. The Registrar shall report to the Vice-Chancellor.

iii To be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Governing Body or the Board, shall commit to his charge.

iv. To conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the University.

v. To Prepare Agenda and issue Notices of meetings of the authorities of the University and all committees and sub-committees appointed by any of these authorities with the approval of the Vice-Chancellor / Chairman of the authorities or Committees.

vi. To keep the minutes of the meetings of all the authorities of the university and of all the committees and sub-committees appointed by

any of these authorities and circulate the same among the members, with the approval of the Vice –Chancellor / Chairmen of the authorities or Committees.

vii. To submit information, reports and documents to the Government and conduct liaison with the Sate Government, Central Government, University Grants Commission and other Government authorities.

viii. To generally supervise the administrative functions of the University.

ix. To supervise and manage the conduct of the Examinations of the University, subject to control of the Vice-Chancellor.

x. To supervise and manage the Infrastructural development and establishment work of the university, subject to the control of the Governing Body or Board of Management.

xi. To supervise and manage the Library and its related activities of the university, subject to the control of the Vice-Chancellor.

xii. To perform such other duties as may be specified by the Board of Management or the Vice-Chancellor from time to time.

5. Remuneration of the Registrar

The Registrar shall draw such emoluments as decided by the Sponsor from time to time.

6. Removal of the Registrar

viii. The Registrar shall hold his office as long as he enjoys the confidence of Vice-Chancellor . The Vice-Chancellor may ask him to relinquish the office by giving three months notice.

ix. The Vice-Chancellor may appoint another person to hold the office of the Registrar with prior approval of Board and decide a date to resume the office of the appointee in such case the outgoing Registrar will cease to hold the office the moment new appointee assumes the charge.

7.0 Appointment, powers and responsibilities of the Chief Finance & Accounts Officer

1: Appointment :

i. The Chief Finance & Accounts Officer shall be appointed by the Vice-Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose.

ii. The selection committee shall consist of:

a. The Registrar.

b. One representative of the Chancellor.

c. One representative of the Sponsor who is also a member of the Governing Body.

d. One expert nominated by the Board of Management, who is not in any way connected with the University.

iii. The Vice-Chancellor may appoint a person to officiate as the Chief Finance and Accounts officer, in the event of temporary absence of the Chief Finance and Accounts Officer.

2. Duties :

i. The Chief Finance & Accounts Officer shall report to the Registrar.

ii. The Chief Finance & Accounts Officer shall exercise general supervision over the funds of the University .

iii. He shall have such powers and responsibilities as may be delegated or assigned to him by the Board of Management or the Finance Committee or the Vice-Chancellor or the Registrar.

3. Qualification Remuneration and Term :

i. The Chief Finance & Accounts Officer shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

ii. The Chief Finance & Accounts Officer shall draw such salary, allowances and entitled to the prerequisites as decided by the Sponsor from time to time.

iii. The term of office and the terms of appointments of the Chief Finance and Accounts Officer shall be as mentioned in his order of appointment by the Vice-Chancellor.

4. Removal of the Chief Finance & Accounts Officer :

i. The Chief Finance & Accounts Officer shall hold his office as long as he enjoys the confidence of Vice-Chancellor . The Vice-Chancellor may ask him to relinquish the office by giving three months notice.

ii. The Vice-Chancellor may appoint another person to hold the office of the Chief Finance & Accounts Officer with prior approval of Board and decide a date to resume the office of the appointee in such case the outgoing Chief Finance & Accounts Officer will cease to hold the office the moment new appointee assumes the charge.

8.0 The Governing Body

The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

1. Constitution of the Governing Body

The Governing Body shall consist of the following members:

i. The Chancellor.

ii. The Vice-Chancellor.

iii. Three persons nominated by the Sponsor.

iv. One nominee of the Government.

v. One educationist of repute to be nominated by the Government.

vi. One academician to be nominated by the Visitor.

2. Term of the Governing Body

i. The members of the Governing Body shall have a term of 3 years.

ii. If in the opinion of the Chancellor, a member of the Governing Body acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with the approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

3. Disqualification of the Members of the Governing Body

The members of the Governing Body shall cease to be members under the following circumstances:

i. If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

ii. If in the opinion of the Chancellor, a member of the Governing Body acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

4. Powers of the Governing Body

The Governing Body shall have the following powers:

i. To appoint Auditors of the University.

ii. To oversee the performance and review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the Act, Rules, Statutes or Ordinances.

iii. To approve the annual report and Accounts of University.

iv. To lay down policies to be followed by the University.

v. To take decision about the voluntary liquidation of the University.

vi. To delegate such powers as it may deem fit to the Board of Management and other authorities or officers of the University.

vii. The Governing Body shall perform such other functions, as it may deem necessary for proper functioning and administration of the University.

viii. Emergency Powers of Governing Body

a. In case of any deadlock in the Board affecting the operations of the University, emergency powers are vested with Governing Body to do all necessary things including superseding the Board and forming a new Board to facilitate smooth functioning of the University.

b. The emergency powers of the Governing Body shall be exercised only when there is a written report sent by the Registrar or any member of the Governing Body to the Chancellor or the Vice–Chancellor about the deadlock in the Board, and when the operations of the University cannot be conducted in the normal course.

c. Upon receipt of such a written report, the Chancellor or the Vice-Chancellor shall direct the Registrar to convene a special meeting of the Board within 7 days, for restoration of normalcy in operations. In the event of Registrar not convening such a special meeting, the Chancellor shall convene such a meeting.

d. The decisions taken by the Governing Body and implemented by the officers under this clause shall be final and binding on all the Members of the board and on all the members of the Governing Body.

5. Meetings of the Governing Body :

i. The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year, on any working day, at the headquarters of the university or any other location as may be agreed by majority of the members. The meetings may be held either by physical presence in one location or through technology-supported virtual meetings.

ii. The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and shall preside over the meetings of the Governing Body. In absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the meeting.

iii. A notice of 7 days shall be given to the members stating the agenda for the meeting. A notice less than 21 days may be considered sufficient if majority of the members agree to such a shorter notice.

iv. The quorum of the meeting shall be 3 members present in person or participating synchronously.

v. Each member of the Governing Body including the presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be adopted by simple majority. In case of a tie, the presiding officer shall have a casting vote.

vi. The presiding officer of the meeting shall cause the minutes of the meeting to be recorded and circulated to the members within a period of 30 days from the date of such meeting.

6. Extraordinary meeting of The Governing Body :

i. In the event of exigency, the Chancellor or the Vice-Chancellor with the concurrence of the Chancellor may call for extraordinary general meeting of the Governing Body.

ii. The Sponsor, may, in the event of exigency and / or in the interest of the administration of the university, request the Chancellor, or in his absence, the Vice-Chancellor either to call for an extraordinary meeting or circulate the resolution among the members of the Governing Body.

iii. The Chancellor or the Vice-Chancellor with the concurrence of the Chancellor, may, under exigencies, obtain the consent of the Governing Body by circulating appropriate resolution among its members, and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Governing Body.

9.0 The Board of Management

The Board of Management shall be the principal executive body of the University.

1. Constitution of the Board Of Management :

i. Following members shall constitute the Board:

(a) The Vice-Chancellor.

(b) The Registrar.

(c) One representative to be nominated by the State Government.

(d) Senior most Professor of the University to be nominated by the Chancellor.

(e) Three representatives to be nominated by the Sponsor.

ii. The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Board and the Registrar shall be the Member Secretary.

iii. The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Board and in the absence of the Vice-Chancellor, the Registrar shall conduct the proceedings of the meeting.

iv. The tenure of the members of Board of Management shall be three years, except in the case of Ex-officio members.

2. Disqualification of the Members of the Board of Management :

The members of the Board of Management shall cease to be members under the following circumstances:

i. If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including

an act of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by by the higher court against conviction.

ii. If in the opinion of the chancellor , a member of the board acts in a way detrimental to the interests of the university, the chancellor may , with approval of the nominating authority , ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

2. Meeting of the Board

i. The Board of the Management shall meet as often as necessary, and at least once in three calendar months.

ii. The meetings shall be called by the Registrar.

iii. A notice of 7 days shall be given for the meeting, provided that an emergency meeting may be convened, at the discretion of the Vice Chancellor, at a short notice.

iv. The quorum of the meeting shall be 3 members present in person or participating synchronously.

v. Each member of the Board including the Chairman / Presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be taken by simple majority. In case of a tie, the Presiding officer shall exercise a casting vote.

vi. The Registrar shall cause recording of minutes of the meeting, with the approval of the Vice-Chancellor and circulate them to the members concerned within a period of 15 days from the date of conduct of the meeting.

vii. The Vice-Chancellor, may, under exigencies, obtain the consent of the Board by circulating appropriate resolution among its members, and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.

3. Powers of Board of Management :

The Board of Management shall have the powers to take all the necessary decisions for smooth and efficient functioning of the University. The powers shall, interalia, include; but not limited to, the following:

i. Financial Powers:

a. To consider the budget as recommended by the Finance Committee and to approve the same with or without modifications.

b. To manage and administer the revenues and properties of the University and to conduct all administrative affairs of the University not otherwise specifically provided for.

c. To manage and regulate the finance, accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents as it may deem fit.

d. To open account or accounts of the university with any one or more scheduled banks and to lay down the procedure for operating the same.

e. To draw, accept, make, endorse, discount and negotiate securities of the Government, promissory notes, bills of exchange, cheques and other negotiable instruments.

f. To issue appeals for funds for carrying out the objectives of the University.

g. To receive grants, donations, contributions, gifts, prizes scholarships, fee and other moneys, and to give grants and donations, to award prizes, scholarships etc.

h. To purchase, take on lease or accept as gift or otherwise any land or buildings or works which may be necessary or convenient for the purposes of the University, and on such terms and conditions as it may deem fit and proper and to construct or alter and maintain any such buildings or works.

i. To acquire intellectual property rights, copy rights, trade marks and the like from any institution or organization, on such terms and conditions as the Board may determine, and pay such compensation for the acquisition as may be just and equitable.

j. To transfer or accept transfers of any movable property on behalf of the University.

k. To execute in consultation with the Holding Trustees (if any) / Sponsor, conveyance, transfer, re-conveyances, mortgages, leases, bonds, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University.

l. To appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit.

m. To invest the funds of the University or money entrusted to the University, in such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment.

n. In consultation with the Holding Trustees (if any) / Sponsor, to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities by providing properties and assets of the University as security, or borrow money without any securities, and upon such terms and conditions as it may think fit, and to pay out of the funds of the University, all expenses, incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed.

o. To maintain and operate the General Fund as stipulated in Sections 7.0 and 8.0 of the Act;

p. To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts including the Balance-sheet for every previous financial year, in such form as may be prescribed by Regulations and submit the same to the Governing Body for its approval.

ii. Powers of Appointments:

a. To create teaching and academic posts and to decide on the number, qualifications and cadres thereof, and to determine the emoluments of such posts.

b. To appoint Directors, Principals, Deans, Professors, Associate Professors and other senior academic and operational staff, as may be necessary.

c. To lay down rules with respect to emoluments and duties for the various academic and non-academic staff recruited by the University.

d. To lay down rules for appointment of Visiting Fellows and Visiting Professors and their emoluments.

e. To appoint internal auditors who shall undertake audit of the various functions of the University.

f. To appoint any external organization / agency with the responsibility of managing the university on behalf of the sponsor.

g. To appoint any external organization / agency to impart training to the employees of the university in various streams of study.

h. To appoint any external organization / agency to provide placements to the students of the university.

iii . Academic Powers:

a. To generally lay down, in consultation with the Academic Council, the academic policies, education and teaching standards and policies relating to students admission, examinations and award of degrees, diplomas and certificates and other academic awards or distinctions.

b. To establish, on the advice of the Academic Council, Division and Departments for the academic work and functions of the University and to allocate areas of Study, Teaching and Research to them.

c. To lay down policy in relation to fee and other charges payable by the students of the University.

d. To institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the Regulations.

e. To lay down rules regarding the emoluments and travelling and other allowances of examiners, moderators, tabulators and such other personnel appointed for examinations, in consultation with the Academic Council and the Finance Committee.

iv. Student Matters and Discipline Powers:

a. To regulate and enforce discipline among the employees and the students of the University and to take appropriate disciplinary action, wherever necessary.

b. To entertain and adjudicate upon any grievance of the employees and students of the University; and to set up Committees for attending to such grievances.

c. To establish and regulate the maintenance of hostels for the students of the University and recognize hostels established by outside parties on the basis of the recommendations of a committee established for the purpose.

v. Administrative and Legal Powers :

a. To approve contracts and works.

b. To create administrative, ministerial and other necessary posts and fix compensation for persons recruited to such posts.

c. To grant leave of absence to the Vice-Chancellor or any other officer of the University and to make necessary arrangements to carry out the functions of such officers proceeding on leave, during their absence.

d. To Conduct inspections and inquiries, in various departments, centres, institutions and affiliated colleges of the University and initiate corrective action wherever needed.

vi. Selection Committee

a. The Board may appoint a selection committee to recommend names of the persons to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professor and such other academic posts as may be prescribed by the Board of Management.

b. The selection committee so appointed shall consist of:

(i) Three experts in the relevant disciplines nominated by the Chancellor.

(ii) One Nominee of the Board of Management not connected with the University.

(iii) Dean of the faculty.

(iv) Two members of Sponsor.

(v) The Vice-Chancellor is the Chairman of the selection committee

vii. Powers to Constitute Advisory Committees :

a. The Board may, with the concurrence of the Chancellor, appoint an Advisory Committee consisting of as many members as necessary for the purpose of providing advice to the Board in matters relating to the conduct of various affairs of the University.

b. The Board may, direct the Academic Council, Finance Committee and / or any other committee set and / or follow the recommendations of the Advisory Board.

c. The Board may define the functions, and powers while establishing such committees.

viii. Powers to Form Sub-Committees:

The Board of Management may form Sub-Committees and / or Ad-Hoc Committees for discharging any of the functions of the Board, by clearly specifying their scope, jurisdiction, authority, powers and functions.

ix. Powers to determine Service Conditions for Faculty members, Officers & others Employees :

a. The Board shall formulate the terms and conditions of appointment and of service of faculty members, officers and employees.

b. The Registrar shall issue the appointment letters to faculty members, Officers and employees in accordance with policies and procedures as formulated by the Board.

x. Powers to delegate Powers :

The Board of Management may, by a resolution, delegate to the Vice-Chancellor, Registrar, Standing Committee or the Ad-Hoc Committee, such of its powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice-Chancellor or the Standing Committee or the Ad-Hoc Committee, or any of their Officers to whom such powers are delegated, shall be reported by them at the next meeting of the Board of Management.

10.0 The Academic Council

The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Regulations have the control over and be responsible for the maintenance of standards of education, teaching and training, inter-departmental co-ordination, research, examinations and tests within the University.

1. Constitution of the Academic Council

i. The Academic Council shall consist of the following members:

a. The Vice-Chancellor.

b. The Registrar.

c. Two Heads of various Institutions under the University to be nominated by the Chancellor.

d. Two faculty members to be nominated by the Chancellor.

e. Two outside experts nominated by the Chancellor.

f. Two members of Sponsor.

g. The Deans by virtue of their office shall be the ex-officio members.

ii. The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

iii. The Vice-Chancellor or Sponsor may invite such other persons, as he may deem fit, to attend the meeting of the Academic Council from time to time. However, such persons invited shall not be eligible to vote on any of the resolution of the Academic Council.

2. Term and Powers of the Academic Council :

Term :

The term of members of the Academic Council shall be two years, except in the case of the employees of the University, who are members of the Academic Council. The term of such members who are employees ends immediately after their relinquishing their office at the University.

Powers :

Subject to the provisions of this Act, Statutes and the Regulations the Academic Council shall have the power to control, regulate and maintain the standards of

education, instruction and examinations of the University and shall exercise such other powers and functions as may be conferred or imposed upon it by this Act, Statutes or the Board.

3. Disqualification of the Members of the Academic Council

i. Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

ii. A member of the Academic Council shall cease to be a member in the following circumstances:

a. If the Member resigns from the Academic Council.

b. If the Member becomes mentally unsound.

c. If the Member had been convicted of a criminal offence including moral turpitude or any other reason, and a higher court has not stayed such conviction.

d. If the Member fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without permission of the Chairman.

4. Meeting of the Academic Council

i. The Academic Council shall meet as often as may be necessary.

ii. One third of the members of the Academic Council present in person or participating synchronously shall constitute the quorum of the meeting of the Academic Council.

iii. Resolutions of the Academic Council may be passed through circulation of such Resolutions among all the members, except in cases where such Resolutions are required to be passed at a meeting convened. The Resolution so circulated and approved by a simple majority shall be effective and binding as if such Resolution had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the Resolution.

5. Functions and Powers of The Academic Council :

Subject to the provisions of the Act, Statutes and the Ordinances, the powers of the Academic Council shall interalia include the following:

i. To report and act on any matter referred or delegated to it by the Board.

ii. To formulate different courses and programs to be imparted to the students of the University.

iii. To lay down the curriculum and frame syllabus for any of the courses and programs offered by the University, and publish text books and other instruction material for the same.

iv. To make recommendations to the Board, with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments, the duties attached thereto.

v. To formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Board as to the expediency of the abolition or sub-divisions of any faculty or the combination of one faculty with another.

vi. To make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University.

vii. To promote research activities and programs, and to ask for, from time to time, reports on such research activities and programs.

viii. To consider proposals submitted by the faculties relating to instruction, teaching facilities, etc.

ix. To appoint committees for admission of students to the University.

x. To recognize diplomas and degree of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University on reciprocal basis.

xi. To approve conferment of degrees, honors, diplomas, licenses, titles and marks of honor on the basis of the results declared.

xii. To make guidelines for the award of fellowships, stipends, scholarships, medals prizes, etc., and empower the Vice-Chancellor or any other officer of the University to approve the eligible candidates for such awards.

xiii. To prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the Act and / or the regulations.

xiv. To make recommendations to the Board of Management on:

a. Measures for improving the standards of teaching, training and research and examinations.

b. Institution of Fellowships, Exchange Programs, Scholarships, Medals, Prizes etc.

c. Regulations covering the academic functioning of the Institute, discipline, residence, admissions, examinations, award concessions, attendance etc and submit the same to the Board of Management for approval.

xv. To suggest measures for departmental co-ordination.

xvi. To appoint committees, consisting of such members as the Academic Council may deem fit, to deal with any of the matters ordinarily dealt with by the Academic Council.

11.0 Examination Committee

1. Constitution of Examination Committee :

i. The Vice Chancellor shall constitute Examinations Committee with respect to each faculty, for the purpose of recommending suitable persons for appointment as examiners and evaluation methods for each subject of faculty.

ii. The examinations Committee shall consist of:

a. The Dean of the Faculty, Chairman.

b. Professor of the subject.

c. One expert in the subject nominated by the Chancellor.

2. Duties and Responsibilities :

i. The examination committee shall recommend a panel of examiners for each subject of the courses of study to the Vice Chancellor.

ii. The Vice-Chancellor shall ordinarily appoint examiners from the panel recommended by the examinations committee, provided that with the approval of the Chancellor he may appoint examiners outside the panel, if he deems fit and necessary. Any Recognized Board / Institution / University / Government Organization as approved by the Chancellor may conduct the examination on behalf of the university.

12.0 Results Committee

1. Constitution of the Results Committee :

i. The Vice-Chancellor shall constitute a Results Committee to approve the results of various examinations before they are declared.

ii. The Results Committee shall consist of:

a. Dean of the faculty concerned.

b. One professor of the subjects assigned to the faculty.

c. One expert nominated by the Chancellor.

d. The Registrar.

2. Duties and Responsibilities :

If in the opinion of the Results Committee the result of any examination is not properly balanced, the Result Committee may recommend action to be taken by the Vice Chancellor.

13.0 The Finance Committee

1. Constitution of the Finance Committee :

i. The Governing Body may appoint Finance Committee.

ii. The Finance Committee shall consist of the following members namely:

a. President of the Sponsor or his nominee.

b. The Vice-chancellor.

c. The Registrar.

d. The Chief Finance and Accounts Officer.

e. Two nominees of the Sponsor.

iii. The President of the Sponsor or his nominee shall be the Chairman of the Finance Committee.

2. Meeting of the Finance Committee :

i. The committee shall meet as often as necessary.

ii. The quorum of the meeting shall be one third of the members of the committee present in person or participating synchronously.

iii. The Chief Finance and Accounts Officer shall call the meeting of the Finance Committee with the approval of the Chairman of the Committee.

iv. A Notice of 7 days shall be given to its members stating the agenda, time and place of the meeting. Provided that the Chairman of the Committee at a shorter notice, can call an emergency meeting.

v. The Registrar shall cause recording of the minutes and resolutions of the meeting and

vi. circulate the same with the approval of the Chairman of the Committee.

3. Powers and Functions of the Finance Committee :

i. To make recommendation on all financial matters to the Board.

ii. To consider all proposals for capital expenditure and to make recommendations to the Board.

iii. To examine the annual accounts of the University and advise the Board.

iv. To examine the annual budget estimate and advise the Board thereon.

v. To review the financial position of the University from time to time and recommend any action to be taken by the Board.

vi. To review the internal controls and act on the comments of the internal auditors.

vii. To make recommendations to the Board on all proposals involving raising of funds, receipts and expenditure.

viii. To determine and fix the fee payable by the students of the University and lay down the procedure therefor; and to fix the basis for charging Consultancy and other fee to be charged by the University.

ix. To generally perform and act on any of the activities that may be delegated by the Vice-Chancellor, or the Board or the Governing Body.

14.0 Standing Committees and/or Ad-Hoc committees

1. Constitution of Standing Committees and/or Ad-Hoc committees :

i. The Governing Body and/or the Board of Management may, at the appropriate time, by a resolution in a duly conducted meeting, and/or in accordance with the directions of the Chancellor appoint standing committees, and / or enquiry committees by defining:

a. The purpose of appointment.

b. The constitution.

c. The tenure of the committee.

d. The financial budget.

e. The procedure to be adopted.

f. The rights and obligations of the committee.

g. The remuneration payable to the members of the committee.

h. The facilities to be acquired and

i. Other matters relevant or incidental to serve the purpose for which it is appointed.

ii. Committees so appointed shall exercise their powers and functions within the delegated authority. Neither the University nor the Governing Body, nor the Board of Management shall be accountable for the authority or powers used outside the scope of delegation by such committees.

iii. Such committees shall be automatically dissolved on completion of their tenure or after completion of the tasks assigned to them by the authority appointing them, unless extension in the tenure is granted by the said authority.

15.0 Budgets

1. The Chief Finance and Accounts officer, with the approval of the Finance Committee, based on the proposed budgets received from different departments, divisions, colleges, institutes of the University, shall prepare an annual budget for the forthcoming financial year, and submit at least two months before the beginning of financial year to the Board, upon the merits may suggest modifications, alterations or additions or approve the same with or without modifications and such approved budget will be the annual budget of the University for the year.

2. No expenditure other than that provided in the budget shall be incurred by the departments, divisions, colleges and institutes of university without the approval of the Finance Committee.

3. The Finance Committee may consider any revision of the Budget based on the recommendation of the Chief Finance and Accounts officer, which shall be placed for ratification of the Board, at a subsequent meeting of the Board.

16.0 Accounts and Audit

1. The accounting year of the university shall be from 1st April of a year to 31st March of the following year.

2. The accounts of the various divisions, departments, institutions and campus(es) of the University shall be consolidated by the Chief Finance and Accounts Officer and he shall make out the annual accounts, consisting of the income and Expenditure Account and the Balance Sheet of the University and place the same before the Finance Committee for their comments. The appropriations of excess of income over expenditure or the absorption of excess of expenditure over the income shall be decided by the Finance Committee. The accounts will, thereafter be adopted by the Board, after which they will be audited by the Auditors appointed by the Governing Body.

3. All the assets of the University shall be maintained in the name of the university and shall be used in the settlement of liabilities at the time of liquidation or closure of university under sections 33 and 34 of the Act.

4. Every balance sheet and income and expenditure account of the University shall comply with the relevant accounting standards as may be prescribed by the Government of India in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards.

5. The Chief Finance and Accounts Officer shall place such audited financial statements before the Governing Body, along with the report of the Auditors for information.

6. The Registrar, thereafter along with the annual report of the University, shall submit such financial statements to the Visitor and to the Government as provided under section 30 of the Act.

17.0 Arbitration in case of disputes

1. The Vice Chancellor shall be responsible for resolution of disputes and grievances between the teachers, officers and other employees and the students of the University.

2. The Vice-Chancellor may delegate the responsibility for arbitration to the Registrar or the Deans of the Faculties as he may deem fit.

3. Any person who is aggrieved of the decision of the Vice Chancellor may appeal to the Chancellor within 15 days of communication of the decision by the Vice Chancellor.

4. Where it is found necessary the Chancellor may appoint an Arbitration Committee to arbitrate such disputes and grievances, with such constitution and such powers as he may deem fit.

4. The procedures for arbitration of disputes shall be laid down by the Board.

18.0 Regulation and Manuals

1. Save as otherwise provided in the Act and the Statutes, the Board may make Regulations, as empowered under Section 37 of the Act, to conduct the business of the University and attain the objectives for which it is established. The Regulations may, interalia, relate to the following:

(i) Number of seats in different programs of the University, not otherwise prescribed for, by any other statutory bodies authorized for the purpose.

(ii) Reservation of seats in different programs of the University not otherwise prescribed for, by any other statutory bodies authorized for the purpose.

(iii) Admission of students.

(iv) Fee and other charges payable by the students.

(v) Examinations and students assessment.

(vi) Award of scholarships, bursaries, fee waivers, etc to students.

(vii) Discipline of students and staff.

(viii) Resolution of disputes among students and staff and procedure for arbitration.

(ix) Conferment of Honorary degree to distinguished persons.

(x) Finance and administration of the University.

2. The Board may appoint an ad-hoc committee to draft the Regulations and to prepare manuals for different departments/functions of the University.

3. The committee appointed above, shall have such members as nominated by the Board and perform all the functions as required under the order of appointment/constitution.

4. On satisfying themselves on the Regulations made out by the committee appointed for the purpose, the Board may adopt them for the University.

5. Each and every authority and officer, teaching and non-technical staff, members of the committees and the students are bound to adhere to the provisions and procedures laid down in the manual of instructions drafted for the purpose.

6. The Board shall have right to alter, amend, frame new rules and regulations, which are not inconsistent with the provisions of the Act for the purpose of conducting the activities of the university for which it is established.

19.0 Ordinances

The Vice Chancellor of the University shall cause the Ordinances of the University to be made as per the provisions of Section 27 of the Act, and shall submit the same to the Government for their approval. He shall make the necessary changes in the Ordinances, as suggested by the Government, and shall table the Ordinances after their due approval by the Government, in the next meeting of the Governing Body. The Vice-Chancellor shall follow similar procedure while making any modifications to the Ordinances, or for introducing new Ordinances.

20.0 Subsequent Statutes

The Governing Body shall make, alter, modify these First Statutes, and the Ordinances as required for the administration of the University and submit the same to the Government for approval.

21.0 University to be open to All Classes, Castes and, Creed

1. The university shall be open to all persons of either sex and of every caste, creed, religion, race, or class or place of domicile or Nationality and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a Teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof;

2. Notwithstanding any thing contained in clause (a) the University shall make special provisions in the Regulations for the employment or protection of educational interests of women, persons with disability or of persons belonging to the weaker sections of the society or Tribals and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes as may be directed by the State Government from time to time.

22.0 Interpretation

1. In the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of the Statute, Ordinances and Regulations, the provisions of the Act shall prevail.

2. The decision of the Governing Body on interpretation shall be final and binding.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-173/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "अंसल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "अंसल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 2nd September 2003

No. F-73-173/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "ANSHAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY VISHVAVIDHYALAYA, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "ANSHAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY VISHVAVIDHYALAYA, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-157/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "क्रिस्टल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "क्रिस्टल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 15th September 2003

No. F-73-157/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "CRYSTAL INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "CRYSTAL INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अगस्त 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1226.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	डभराखुर्द प.ह.नं. 19	0.121	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 2, चांपा.	चांपा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अगस्त 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1228.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सिलादेही प.ह.नं. 21	0.959	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 2, चांपा.	बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2003

क्रमांक 02/भू-अर्जन/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	ग्राम-पथरी दा. खुड़मुड़ी प. ह. नं. 84	1.860	डिप्टी चीफ इंजीनियर (एस. एण्ड सी.) दक्षिण पूर्व रेल्वे, रायपुर.	ग्राम पथरी उप. तहसील धरसीवां तहसील रायपुर की निजी भूमि को दक्षिण पूर्व रेल्वे की तीसरी लाईन के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2003

क्रमांक 85/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/11/अ/82-2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	खैरझिटी	0.26	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. क्र. 3, रायपुर.	सरगोड़ से खैरझिटी मार्ग निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2003

क्रमांक /क/वा. 1/अ.वि.अ./6 अ-82, 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	खमतराई प.ह.नं. 108	0.035	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, रायपुर संभाग.	रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर खमतराई के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

प्र. क्र./13/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	ढनढन	1.803	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2003

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने का लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	भेड़िया	3.23	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग, प्रतापपुर.	भेड़िया जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक 355/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सैहामालगी	3.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला दुर्ग.	हेम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक 355/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	निंगापुर	9.53	कार्यपालन अभियंता, मनियारी संभाग, मुंगेली, जिला बिलासपुर.	फोंक व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/ सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बायंग प.ह.नं. 5	0.373	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	उप-शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/ सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मौहापाली प. ह. नं. 20	0.299	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भ/स रायगढ़.	रायगढ़ लोइंग मौहापाली मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक 1752/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	चारभाठा प.ह.नं. 25	4.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डूब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितंबर 2003

क्रमांक 1755/अ.वि.अ./भू-अर्जन/7-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	पड़रीपानी प.ह.नं. 25	0.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक 1756/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	डोंगरीपाली प.ह.नं. 25	0.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक 1753/अ.वि.अ./भू-अर्जन/9-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	जोगीदादर प.ह.नं. 23	0.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक 1832/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	भगत सरायपाली प.ह.नं. 25	0.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक 1757/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	रिमजी प.ह.नं. 23	4.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक 1751/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	कुरमीपाली प.ह.नं. 25	4.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.).	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक 1264/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धा . 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-खुड़मुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
802	0.63
805/1	0.25
806	0.25
1267	0.70
940	0.15
881	0.15
908	0.30
918	0.15
941	0.20
1000/1	0.10
994	0.18
1038	0.18
1041	0.05
1166	0.35
805/2	0.20

(1)	(2)
805/3	0.15
1270	0.20
1266	0.10
882	0.07
883	0.30
878/1	0.05
942	0.22
939	0.25
1000/2	0.15
1037	0.15
1043	0.15
1042	0.07
1155	0.22
1276/1	0.20
1276/2	0.02
1271	0.07
870	0.25
982	0.30
906	0.20
909	0.25
984	0.05
999	0.05
995	0.10
1045	0.18
1046	0.10
1044	0.05
1154	0.20
योग 42	7.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अति. सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्र. 846/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरमाल, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.962 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10.	0.166
206/1, 206/2, 206/3, 206/4	0.109
205	0.073
278	0.089
279	0.077
275	0.008
274	0.125
273	0.004
287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6,	0.210
288	0.101
योग	0.962

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरमाल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 89/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भडोरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.082 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
591/1	0.053
591/2	0.008
587/4	0.105
592	0.060
613/2	0.053
613/3	0.020
613/1	0.105
614	0.073
615/3	0.129
615/4	0.036
617/2	0.101
618, 619, 620	0.210
628	0.069
629/2, 627	0.060
649/1	0.032
649/3	0.057
650	0.101
649/4	0.049
680/1	0.036
680/2	0.040
680/3	0.040
680/4	0.109
681	0.036
682/1	0.060
682/2	0.065
682/3	0.040
684/7	0.020
696/2	0.020
697/2, 697/3, 498	0.178
699/2	0.085
692	0.032
योग	2.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भडोरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 90/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.667 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331/6	0.008
331/4	0.012
330/2	0.008
330/1	0.138

(1)	(2)
330/3	0.183
271	0.045
272/2	0.042
839	0.231
योग	0.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुक्ता माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 91/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
737/1, 737/2	0.085
735/1	0.037
735/4	0.028
585/1	0.081
496/3	0.053
500/3	0.040
545/2	0.093
584	0.117
583/1	0.065
583/2	0.046
495/2	0.077
494/2, 494/3	0.158
499/2	0.089
500/2	0.040
517/1	0.016
517/2	0.020
501/3	0.061
501/2	0.040
501/1	0.040
507	0.032
502	0.008
503, 504	0.065
505	0.020
188	0.077
189	0.069
734	0.409
योग	1.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिरदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 92/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
385/1	0.265
385/2	0.070
389/1	0.056
389/7	0.106
389/9	0.232
399/1, 399/2	0.188
402/4	0.002
402/5	0.112
402/6	0.163
402/7	0.095
402/8	0.108
405/1	0.170
407/1	0.043
407/2	0.058
408/1	0.038
408/2	0.048
446	0.024
416	0.126
418/2	0.013
419/2	0.008
433/1	0.084
433/2	0.101
433/3	0.049
436/1	0.074
436/2	0.181
436/3	0.024
436/4	0.041
437	0.388
438/1	0.049
438/3	0.032
439/7	0.040
444/1	0.098
445/1	0.129
445/2	0.056
448/1	0.102
448/2, 448/3	0.141
योग	3.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 93/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.901 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
892/3	0.113
55/2, 4, 5	0.093
55/6, 55/7, 8	0.073
55/1	0.129
790/6	0.081
790/11	0.040
795	0.020
805/1	0.044
805/2	0.044
806, 807	0.028
770/50	0.081
803/2	0.044
800/2	0.036
800/1	0.057
770/42	0.124
820/1	0.065
864/1	0.134
864/2	0.227
866/1, 2	0.008
859	0.085
858, 876/1	0.154
856/2	0.028
871/2	0.023
872/1	0.004

(1)	(2)
855/1	0.036
876/2	0.081
860	0.065
857/8	0.057
857/2	0.158
857/13	0.008
853/6, 853/7	0.036
855/2	0.032
854/1	0.008
854/2	0.016
134/2. 134/3, 134/4	0.049
134/5	0.069
132/2	0.032
131/3	0.069
131/1	0.069
131/2	0.057
130/2	0.077
129/3	0.040
129/2	0.053
127/1	0.073
123/5	0.081
योग	2.901

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाधापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 94/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-उच्चपिंडा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.455 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
291	0.004
292/3	0.081
292/2	0.004
292/1	0.008
293/5	0.121
285	0.020
293/1	0.073
281	0.061
282	0.032
280	0.049
130	0.004
263	0.008
132	0.016
262	0.121
261	0.085
159/1	0.150
160	0.020
159/2	0.004
161	0.053
164	0.057
163/3	0.044
163/1	0.016
163/2	0.016
234	0.105
233/2	0.045
233/1	0.045
230/2 क	0.024
232/2	0.024
232/1	0.020
230/2 ख	0.028
231	0.012
220	0.105
योग	1.455

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केनापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 95/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.806 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.020
303	0.097
304/2	0.117
289/1	0.040
289/2	0.069
283/1	0.117
251	0.036
276/5	0.061
276/4	0.093
264/2	0.061
264/1, 275/1	0.045
261	0.129
265/2	0.008
226/1	0.053
222/28	0.012
263	0.032
249	0.061
248/1	0.069
284/4	0.012
	0.061
225/14	0.036
226/5	0.053
222/27	0.012
225/17	0.008
225/6	0.036
250/1	0.036
225/3	0.081
229/1	0.053
228/6	0.077
222/6	0.049
222/4	0.054
226/1	0.049
287	0.069
योग	1.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोड़ासागर माइनर (सिंघरा) + सेरो सब डिस्ट्री ब्यूटर से)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 96/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बंजारी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.178 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4, 5	0.141

(1)	(2)
3/1	0.145
14/3	0.085
14/4	0.057
14/1	0.061
14/5	0.145
55	0.117
56/1	0.113
54/5	0.004
54/4	0.053
66/3	0.049
57/3	0.129
66/2	0.032
130	0.178
129/1	0.061
134/8	0.036
135/1	0.049
135/2	0.049
136, 138	0.040
137	0.036
149	0.045
100	0.097
99	0.036
342/2	0.008
342/1	0.117
341/2	0.016
343/1	0.101
343/2	0.089
344	0.089
योग	2.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिमगांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 97/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-सेन्दुरस, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.816 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
399/3	0.073
399/1	0.114
400	0.116
418	0.057
416/2	0.032
415/2	0.049
414/4	0.089
412/4	0.004
413/1	0.057
410/1	0.097
509/4	0.130
510/3	0.028
504/4	0.020
504/8	0.024
504/3	0.020
511/5-6	0.073
518/1, 2	0.077
519/3-4	0.044
519/2	0.044
523/2	0.162
523/7	0.057
523/5	0.053
523/4	0.081
524/2	0.020
524/1	0.170
526	0.125
योग	1.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 98/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
पोता उप वितरक नहर	
19/2, 3, 5, 6, 8	0.011
20	0.210
22	0.069
30/1	0.101
75/1	0.215
76	0.004
74/4	0.077
72/2	0.085
70/1	0.101
71/2	0.134
61, 62	0.247
57/3	0.049
60	0.053
59	0.045
58/3	0.097
120, 122	0.036
125/1, 123	0.101
125/1	0.174
155	0.620
154/1	0.012
168/4	0.138
168/3	0.166
168/1	0.287
168/2	0.093
171/3	0.028
171/2	0.089
171/1	0.028
171/14	0.162
171/4	0.085
171/5	0.101
171/6	0.107
योग	4.725
सारसडोल माइनर	
19/1, 2, 5	0.158
629/2	0.218
योग	0.376
कुल योग	5.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक एवं सारसडोल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 99/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं.10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.633 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1017/1, 1017/2, 1017/3	0.040
1000	0.032
1015	0.008
1014	0.032
1004/, 1, 2, 3	0.032
1013/1, 2, 3	0.081
1012	0.081
1008	0.081
1007	0.065
948	0.065
949	0.121
945	0.085
944	0.085
943	0.040
926	0.008
927	0.065
928	0.073
929	0.020
933, 932	0.129
915	0.138
911/2, 912, 380/1, 380/2, 911/1	0.202
381, 382, 385	0.085
383/1, 382/2	0.121
377	0.101
358	0.125
359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5	0.146
266/1, 266/2	0.085
265/1, 265/2	0.073
264	0.129
263	0.081
262	0.040
261/1, 261/2, 261/3	0.065
271	0.057
272	0.036
273	0.093
276/1, 276/2, 276/3	0.032
337/1, 337/2	0.028
338/1, 338/2, 338/3	0.162
443	0.081
444	0.012
441	0.032
442	0.008
440	0.069
437	0.040
436	0.036
437	0.012
428	0.081
426	0.049
526/1,2,3,4,5	0.065
527/1, 2	0.040
652	0.097
425	0.053
435	0.016
योग	3.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुआ डेरा माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 100/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं.3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.251 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रक़बा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) पासीद माइनर	
112/1	0.077
112/2	0.089
94/1 ख	0.045
861/1	0.028
92	0.069
476	0.107
477	0.064
478	0.096
853	0.053
852	0.008
855	0.008
480/1 क	0.048
480/1 ख	0.070
480/1 ङ	0.039
518	0.092
862/2	0.105
657	0.251
521/5	0.184
656	0.138
652	0.109
643	0.016
644/1	0.020
644/2, 644/3	0.053
646/2	0.016
640	0.057
645/2	0.012
638/1	0.089
336/1-2	0.065
637	0.073
635/1 क	0.093
635/1 ख	0.036
635/1 ग	0.092
864/2	0.138
869	0.081
862/1	0.071
684/3 ख	0.012
864/4	0.053
862/2-3	0.161
519	0.047
योग	2.865
(ब) पासीद सब माइनर	
628/3	0.068
849/1 क, 849/2 क	0.068
844/1	0.029
844/2 क	0.101
850/2	0.032
850/3	0.028
843/2	0.060
योग	0.386
कुल योग	3.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद माइनर एवं पासीद सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 101/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-आमनदुला, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.927 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1773	0.056
1774/1	0.053
1774/2	0.053
1774/3	0.040
1779/3	0.061
1780	0.053
1779/4	0.024
1778	0.053
1781	0.053
1782	0.044
1783	0.044
1789/2	0.049
1791	0.053
1787/2	0.024
1792/1	0.053
1797	0.077
1798/2	0.077
1799/1	0.053
1800	0.085
1802	0.085
1803/1	0.020
1804/3	0.149
1713/1	0.081
1715/1	0.016
1714/1	0.073
1713/3	0.057
1711/4	0.057
1711/6	0.053
1711/2, 3	0.073
1698/2	0.053
1714/2	0.004
1699	0.081
1700	0.154
1670/2	0.085
1670/1	0.053
1687	0.081
1671	0.061
1685/1	0.121
1680/1	0.044
1680/2	0.053
1680/4	0.040
1681	0.020
1678	0.020
1677	0.053
1679	0.040
1669/2	0.053
1669/1	0.020
589	0.186
615	0.016
616	0.020
योग	2.927

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 102/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
458/1	0.024
461, 462	0.112
480/1	0.016

(1)	(2)
480/2, 480/3	0.052
464	0.120
450/1, 451	0.064
452, 453	0.072
455/2	0.044
454/2	0.040
450/2	0.048
458/2	0.052
459	0.040
460/2, 460/3	0.032
463	0.068
474	0.044
465/2	0.040
467	0.052
466/1	0.056
619	0.036
616	0.024
617	0.048
622/10	0.056
622/1	0.076
622/3	0.060
641/3	0.068
636/1	0.072
635/3	0.071
622/5	0.060
621	0.004
623	0.056
624/2	0.052
624/4	0.076
639/1	0.012
625	0.024
636/2	0.016
636/4	0.068
635/4	0.012
635/1	0.068
628/14	0.052
628/12	0.048
628/11	0.056
628/8	0.024
628/3	0.004
628/4, 628/7	0.132
629	0.088
768/3	0.084
768/2	0.012
768/1	0.084
793/7	0.008
769/3	0.084
769/2	0.052
योग	2.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 103/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-नगझर, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.371 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1011/1	0.040
1011/2	0.073
1012/2	0.032
1008	0.008
804/2	0.004
1007/2	0.032
1006	0.040
1002/1, 2	0.082

(1)	(2)
1003/3	0.177
727/1	0.036
728	0.036
729/2	0.049
729/1	0.089
835/1	0.004
735/2	0.028
735/1	0.036
743	0.016
742/2	0.061
741/1	0.028
740	0.036
739	0.089
751/2	0.138
784/3	0.045
783	0.093
831/2	0.040
803/1	0.065
835/2	0.057
803/2	0.073
835/3	0.065
835/6	0.057
833/1	0.137
800	0.073
831/5	0.040
831/4	0.097
847/1	0.040
848/1, 850	0.069
849	0.012
857/1	0.004
857/3	0.040
860/3	0.097
858, 859	0.077
861	0.032
857/4	0.024
योग	2.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 104/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चरौदा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.515 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
187/2, 3	0.121
187/1	0.125
187/4	0.110
195/17	0.090
195/23	0.004
178/1	0.078
212/4	0.076
174/6	0.132
212/2	0.090
174/3	0.088
174/9	0.050
174/1	0.328
151/2	0.090
151/7	0.016
151/1	0.012
151/11	0.094
151/1	0.028
124/1	0.115
139	0.004
138	0.048
124/6	0.104
301/3	0.155
301/4	0.128

(1)	(2)
304/2	0.096
398	0.040
395/4	0.036
395/2	0.035
405/1	0.016
405/2	0.016
411/6	0.056
411/7	0.051
417/2	0.280
418	0.040
417/1	0.040
91	0.133
59/2	0.170
59/3	0.064
59/4	0.080
87/1	0.170
87/1	0.206
87/2	0.004
78/1	0.014
78/2	0.126
76/1	0.117
76/1	0.073
76/2	0.068
72/1	0.040
72/3	0.069
72/2	0.077
68/2	0.050
71/5	0.008
69/1	0.165
26/1से 5	0.036
25/1	0.101
25/2	0.060
21/3	0.052
21/5	0.056
41	0.162
34/2	0.081
40/2	0.089
39/3	0.037
38/3	0.060
38/5	0.060
48	0.081
47/3	0.016
47/6	0.113
47/5	0.012
47/2	0.065
47/9	0.008
योग	5.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चरौदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 105/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.784 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/7	0.081
1/1	0.065
1/6	0.004
1/5	0.049
220	0.020
1/8 ख	0.053
1/8 क	0.041
1/8 ग	0.024
2	0.045
61	0.008

(1)	(2)
4/1	0.069
4/2	0.012
3/1	0.004
3/2	0.024
51/1 ग	0.020
51/1 घ	0.020
51/1 ख	0.061
51/1 ड	0.016
576/2	0.045
577/1	0.036
51/1 घ	0.146
65/2	0.085
704, 65/1	0.053
63	0.004
62	0.077
574/4	0.049
58/2	0.126
58/1, 3	0.077
54/4	0.032
79	0.020
194, 195/1	0.093
196/2, 197/2	0.008
195/3	0.004
208/2	0.057
209/5	0.057
568, 569/1, 570/1, 2	0.077
208/1	0.004
209/3	0.061
215/1	0.049
208/2	0.012
214	0.097
574/5	0.040
537/4	0.032
216/5	0.089
216/8	0.105
575/2	0.041
218/8	0.065
219	0.065
564	0.036
569/2	0.036
573/2	0.045
577/2	0.032
576/1	0.036
539/1	0.036
539/2	0.020
538/1	0.028
538/2, 3	0.040
537/10	0.024
537/14	0.024
537/13	0.032
537/7	0.049
523/5	0.020
521/1	0.004
योग	2.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 106/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नगझर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339/1	0.028

(1)	(2)
339/2	0.057
330/2	0.024
329/1	0.040
327/3	0.004
324	0.061
327/2	0.061
327/4	0.032
323/1	0.097
321	0.081
322	0.012
314/1	0.040
314/2	0.057
284/2	0.032
313/3	0.036
299/1	0.117
299/2	0.053
265	0.014
299/3	0.012
298	0.061
295/1	0.036
295/2	0.061
284/1	0.053
283/1	0.020
283/2	0.065
263/2 ख	0.040
264	0.049
योग	1.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 330/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेमुड़पार, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.006 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
621/1	0.222
154/1	0.016
607/9	0.121
607/10	0.044
607/8	0.008
607/5	0.105
607/11	0.085
623/1	0.157
624/3, 4	0.016
624/1	0.056
605/5	0.040
605/4	0.040
606/1	0.048
605/1	0.024
605/12	0.121
604/7	0.072
605/2	0.012
604/13	0.053
604/4, 604/29	0.072
605/13	0.141
605/11	0.036
604/9	0.016
600	0.129
642/3, 595/1	0.072
505/2	0.032
245/1	0.125
598/1, 2, 599/2	0.032
489/4	0.072
598/3, 599/1	0.008
492/3, 4	0.149
596	0.267
442/1	0.157
442/4	0.012

(1)	(2)
443/5	0.174
443/6	0.068
443/4, 8	0.032
489/1	0.129
493/5	0.303
502/1	0.032
504/2, 3	0.101
502/2	0.238
515	0.064
164/1	0.230
514/2, 3, 4	0.076
513	0.105
238/2	0.028
238/1	0.060
239/3	0.060
239/2 क	0.052
239/2 ख	0.012
239/4 ख	0.016
239/6	0.040
246/2	0.129
246/3	0.105
246/4	0.040
245/2	0.008
162/2 क	0.076
161/4	0.024
163/3	0.061
162/3	0.028
163/5, 6	0.283
165, 166/3	0.036
154/3	0.048
150/1	0.032
150/3	0.020
154/2	0.089
150/2	0.097
151	0.093
144, 146	0.271
145/16	0.020
720/2	0.166
योग 71	6.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़ेमुड़पार सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अप्रैल 2003

क्र. 98/अ-82/02-03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बरभांठा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.557 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
208/2	0.057
205/1, 2	0.057
203/2	0.121
97	0.032
202/2	0.053
202/1	0.016
206	0.069
113/1	0.012
83/1	0.093
199/1	0.138
110/2	0.065
147/4	0.061
148	0.061
145	0.105
144/1	0.194
143/1	0.057
112/107	0.194
113/2	0.081
95/1	0.061
85/4	0.121
83/2	0.024
88	0.085
226	0.073

(1)	(2)
221/1	0.012
207	0.028
210	0.154
225	0.121
223	0.097
224/1	0.036
220	0.154
222/1	0.028
200/7	0.040
200/8	0.057
योग	2.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भातमाहुल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 मई 2003

क्र. 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-पामगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-रींवापार, प. ह. नं. 19
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.923 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
266	0.081
301/2	0.004
302	0.020
301/1	0.024
304/3	0.016
300/2, 300, 298	0.117
299/1	0.024
304/1	0.077
317/1	0.016
297/3, 376/2	0.065
318	0.101
319, 398, 399	0.073
324, 378/2	0.032
323	0.020
374, 375, 376/1	0.085
401/1	0.020
400	0.032
396	0.008
395	0.008
394	0.008
391	0.028
390	0.024
389	0.024
388	0.016
योग 24	0.923

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राहौद से खोखरी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2003

क्रमांक क/वा. 1/अ. वि. अ./01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कुहेरा, प. ह. नं. 70/17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
329	0.372
योग	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झांझ नवागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 मई 2003

क्रमांक 17 अ-67/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लटोरी, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134/1	0.40
134/2	0.61
134/3	0.40
134/4	0.040
योग 4	1.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा भूमिगत खदान में एयरसाफ्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.